क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 340, बुधवार, 09 जनवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर सरकार ने बढ़ाया राज्यसभा सत्र, विपक्ष का हंगामा

नेशनल डेस्क। सवर्ण आरक्षण बिल पेश किए जाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सत्र का एक दिन बढ़ाए जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध जताया है। विपक्ष के नेताओं का कहनाहै कि राज्यसभा का सत्र बढ़ाने के लिए आम सहमति नहीं ली गई। विपक्ष के नेताओं ने मंगलवार को संसद परिसर में ही विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव समेत कई नेताओं ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक प्रस्तावित था, जिसमें दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) की कार्यवाही 8 जनवरी के बाद स्थगित हो जाती। लेकिन मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधी बिल पेश करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यसबा का सत्र बुधवार तक के लिए बढ़ाया है, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा है। ।

अपना दल को अपनाने की तैयारी में अखिलेश यादव

लखनऊ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति हर रोज नया रंग दिखा रही है. बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार अपने खेमे की मजबूती में जुटे हैं. राजनीतिक रूप से बेहद अहम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में को बड़ा झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी खास फॉर्मूला तैयार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक सपा अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस और कृष्णा पटेल के अपना दल को एक साथ महागठबंधन में लाने के लिए तैयार किया है. सपा अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को गठबंधन में शामिल करके और कृष्णा पटेल को अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की पेशकश कर सकती है. समाजवादी पार्टी ह्ष्ठ के सभी सहयोगियों को महागठबंधन के खेमे में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. कृष्णा पटेल सपा-बसपा से भी बातचीत में होने की बात पहले ही कह चुकी हैं. अनुप्रिया और आशीष पटेल भी को हालात न सुधारने पर छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं. कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया के साथ एक गठबंधन में जाने के सवाल पर संकेत दिया था. उन्हें बेटी के साथ किसी गठबंधन का हिस्सा बनने में आपत्ति नहीं होगी. मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल सहित के साथ अन्य छोटे दलों ने मिलकर गठबंधन बना रहे हैं. हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल एनडीए का हिस्सा थी. चुनाव में अपना दल को दो सीटें आई थीं. केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में सहयोगी पार्टी अपना दल-सोनेलाल ने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को आगाह करते हुए कहा कि वह सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार सुधारे नहीं तो पार्टी 'कोई भी निर्णय' ले सकती है. अपना दल-सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वह इसका धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रही है. मगर उत्तर प्रदेश में पार्टी को बीजेपी से वह सम्मान नहीं मिल रहा है.

सवर्ण आरक्षण:

सवर्ण आरक्षण: लोकसभा चुनाव में इससे भाजपा को फायदा होगा?

नेशनल डेस्क ।

भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण का बिल पेश करने के बाद इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक भी पेश कर दिया है, जबकि इसे पारित करा पाना उसके लिए असंभव ही होगा। संविधान में संशोधन का विधेयक इसलिए पेश किया गया, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के भाजपा के प्रस्ताव का चुनावी मौसम को देखते हुए कांग्रेस समेत तमाम दलों ने विरोध नहीं किया, यद्यपि इसे चुनावी स्टंट जरूर बताया। यह अलग बात है कि मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संसद में बिल पेश किया है, पर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात पहले से उठती रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, जिनमें 10 फीसदी सीटें सवर्ण बहुल हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये कुल आबादी का 20 प्रतिशत हैं। सवर्णों में भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा हैं जो कुल आबादी का करीब 10 प्रतिशत हैं। भाजपा मुख्य रूप से सवर्णों और ब्राह्मणों की ही पार्टी मानी जाती है। भाजपा के करीब तमाम नेता, खासकर उत्तर प्रदेश के ऊंची जातियों से ही संबंध रखने वाले हैं। भाजपा नेतृत्व को यह उम्मीद है कि सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कर वह सवर्णों का वोट आसानी से ले सकती है। साथ ही, इसका दूसरे राज्यों में भी उसे फायदा मिल सकता है, पर सभी को यह भली-भांति मालूम है कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिला पाना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि 8 जनवरी को संसद के सत्र आखिरी दिन है। यह मोदी सरकार के लिए भी संसद का आखिरी सत्र है। लेकिन सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं नौकरियों में 10 आरक्षण प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया। इसे मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा साफ तौर पर कहेगी कि उसने सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए बिल तो पेश किया ही, इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक भी पेश कर दिया। उल्लेखनीय है कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की, लेकिन 1992 में कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। इसके पहले 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जातियों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद सवर्णों को भी 3 प्रतिशत आरक्षण दिया था, पर कोर्ट ने इसे भी खत्म कर दिया था। जहां तक राज्यों का सवाल है, 2016 में गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। 2015 में राजस्थान सरकार ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों में 17 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया था, पर कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था।

बहरहाल, माना यह जा रहा है कि सवर्णों को आरक्षण मिलना भले ही संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं हो सकेगा और यह एक शिगूफा होकर ही रह जाएगा, पर भाजपा को इसका लाभ जरूर मिलेगा। यह भी नहीं भूला जा सकता कि एससी/एसटी एक्ट लागू हो जाने के कारण सवर्ण मतदाताओं में भाजपा के प्रति नाराजगी रही है और विधानसभा चुनावों में भी इसका असर %नोटा% के रूप में देखने को मिला है। विधानसभा चुनावों में नोटा ने भाजपा को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए बिल पेश किए जाने को इस रूप में देखा जा रहा है कि भाजपा नाराज सवर्ण मतदाताओं को मनाना चाहती है। वैसे भी भाजपा का आधार सवर्णों में रहा है। उल्लेखनीय है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सामान्य वर्ग के 35.3 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 25.5 प्रतिशत वोट मिले थे। 2014 में भाजपा को सामान्य वर्ग के सबसे ज्यादा 47.8 प्रतिशत वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 13.8 प्रतिशत ही मत मिले। समझा जा सकता है कि सवर्ण मतों का भाजपा के लिए कितना महत्व है।

ये जहां अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की नैया को पार लगा सकते हैं, वहीं इनका मत नहीं मिलने से भाजपा को अपने परंपरागत वोटों का भी नुकसान उठाना पड़ेगा।

लोकसभा में बोले राजनाथ, सिटीजनशिप संशोधन विधेयक सिर्फ असम के लिए नहीं है

नई दिल्ली । लोकसभा में सिटीजन चार्टर बिल 2016 में बहस के दौरान केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक सिर्फ असम के लिए या किसी खास देश से आने प्रवासियों की बेहतरी के लिए नहीं है. यह बिल उन प्रवासियों के लिए भी है, जो पश्चिमी सीमाओं से आए हैं और राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में बस गए हैं. बहस के दौरान कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया. लोकसभा में बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एनआरसी के प्रति कटिबद्ध हैं. एनआरसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. गैरकानूनी तरीके से देश में आने वाले लोगों से (प्रवासियों) निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि असम के लोगों के अधिकार, संस्कृति और रोजगार सुरक्षित है. एनआरसी में कोई भेदभाव नहीं है. राजनाथ ने कहा कि सरकार असम और बोडो लोगों के मुद्दों को उठा रही है. सरकार ने लंबे समय से लंबित मुद्दों के निवारण के उपाय किए हैं. वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए।

उन्होंने बहस के दौरान असम में दंगों और विरोध का हवाला भी दिया. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इसे फिर से सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जा सकता है।

अयोध्या मामले में रोजाना हो सकती है सुनवाई, मामले के निपटारे तक रोज बैठती है संविधान पीठ

नई दिल्ली ।

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है. इस मामले पर 10 जनवरी से सुनवाई शुरू हो रही है. अब इस मामले को संविधान पीठ के हवाले कर दिया गया है. 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. अगर परंपरा पर नजर डालें तो इस मामले में अब रोजाना के आधार पर सुनवाई हो सकती है. मामले को पाँच जजों की बेंच सुनेगी जो संवैधानिक बेंच है. संवैधानिक बेंच जिस दिन बैठती है उस दिन उस कोर्ट में अन्य मामले लिस्ट नहीं होते हैं. संवैधानिक पीठ पूरे दिन एक ही मामले पर सुनवाई करती है. परंपरा यही है कि वह बेंच मामले का निपटारा होने तक रोज़ाना बैठती है. पीठ मामले को लगातार सुनकर निपटाती है. यह सुनवाई यानि मंगलवार, बुधवार व गुरूवार होते हैं. संवि धान चीफ जस्टिस रंजन गोगाई 5 जजों की बेंच के हेड होंगे. इस बैंच में चीफ जस्टसि रंजन गोगोई के अलावा जस् टसि एसए बोबडे, जस्टसि एनवी रमना, जस्टसि यूयू ललित और जस्टसि डीवाई चंद्रचूर्ण शामिल होंगे. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या टाइटल विवाद में फैसला दिया था.फैसले में कहा गया था कि विवादित लैंड को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए.जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए.सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए जबकि बाकी का एक तिहाई लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.वहीं, दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी थी. इसके बाद इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई थी.सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी.कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.।

मोदी ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री से की मुलाकात, संबंधों को नई दिशा देने का लिया संकल्प

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की अपनी समकक्ष एर्ना सोलबर्ग के साथ सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में सहयोग तथा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के तरीकों पर चर्चा की. पीएम मोदी और सोलबर्ग ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और सम्पूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. पीएम मोदी ने सोलबर्ग के साथ बातचीत के बाद एक बयान में कहा कि हमने अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा तथा दिशा देने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि उन्होंने सागरीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर सार्थक चर्चा की. भारत और नॉर्वे के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहयोग है. दोनों देश के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, बहुस्तरीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर करीबी समन्वय है. सोलबर्ग सोमवार (07 जनवरी) को यहां पहुंची थीं. उनका मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया. । नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई. उधर, अधिकारियों ने बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी सोलबर्ग से वार्ता की और दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने पर विचार साझा किए.

नागरिकता विधेयक पारित होने के बाद भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा

गुवाहाटी । लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने इसके विरोध में मंगलवार को पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया। इस विधेयक के विरोध में बोरा पहले ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके विरोध में भाजपा छोड़ी है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को अपना त्यागपत्र सौंपा है। बोरा ने अपने त्यागपत्र में लिखा है, 'मैं नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं । मैं सही अर्थों में महसूस करता हूं कि इससे असमी समाज को हानि होगी।' उन्होंने कहा,'यह विधेयक असमी समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा। इसलिए मैं लगातार इसका विरोध करता आ रहा हूं।' बोरा ने कहा, 'लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद मैं भाजपा से सहमत नहीं हो सका और इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे

शक्ति ऐप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछेंगे राहुल गांधी, किसे बनाएं दिल्ली का अध्यक्ष?

नेशनल डेस्क ।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अजय माकन के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी दिल्ली जैसे महत्पूर्ण राज्य का जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। संभावितों में शीला दीक्षित, जेपी अग्रवाल से लेकर कई युवा नेताओं का नाम चर्चा में चल रहा है। इसी बीच मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खुद पूछेंगे कि दिल्ली की कमान किसे सौंपी जाए। इसके लिए पार्टी के शक्ति ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी पार्टी के निम्नतम स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करना चाहते हैं। वे कार्यकर्ताओं को यह एहसास भी दिलाना चाहते हैं कि वे पार्टी के शीर्ष निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनकी आवाज खुद कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा सुनी जा रही है। इसी कोशिश के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से शक्ति ऐप पर फोन करके पूछा जाएगा कि किसे दिल्ली का अध्यक्ष बनाना सही होगा। कांग्रेस दिल्ली प्रभारी पीसी चाको ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी 10 जनवरी के बाद विदेश जा रहे हैं और उनके विदेश जाने के पहले की अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। अजय माकन के इस्तीफे को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच होने वाले संभावित गठबंधन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि माकन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूर्व में उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर करोलबाग में इस बात की स्पष्ट घोषणा की थी, कि वे खुद और पार्टी कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर आप के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है।

एसपीओ की भर्ती लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर कठुआ में धरना प्रदर्शन

कठुआ । राज्य पुलिस विभाग में एस.पी.ओ. की भर्ती देखने वाले कठुआ के युवाओं ने भर्ती लिस्ट जारी करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर मंगलवार को युवाओं ने ड्रीम लैंड पार्क परिसर में धरना देकर आवाज बुलंद की। धरने की अगुवाई कर रहे बार्डर यूनाइटेड फ्रंट के घनिश्याम शर्मा ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार बेरोजगारी को दूर करने के दावे करती है लेकिन रोजगार देने के नाम पर युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पिछले करीब एक साल से यह युवा भटक रहे हैं और माग कर रहे हैं कि जिला कठुआ की पुलिस विभाग की एस.पी.ओ. की लिस्ट को जारी किया जाए लेकिन लिस्ट जारी करने को लेकर कोई प्रयास नहीं हो पाए। उन्होंने केंद्र सरकार सहित भ्भाजपा के नुमाइंदों को कोसते हुए कहा कि बार बार युवाओं ने उनसे भी गुहार लगाई लेकिन युवाओं को इंसाफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आठ हजार एस.पी.ओ. लगाया गया जबकि वही लोग बाद में पत्थरबाज और आतंकवादी बन जाते हैं जबकि यहां भारत माता की जय कहने वाले युवाओं को नौकरी के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह भी कहा जा रहा है कि इनकी लिस्ट गुम हो गई हैं ।

अज्ञात लोगों ने बीजेपी, माकपा कार्यकर्ताओं के घरों को बनाया निशाना

कोझिकोड ।

केरल में सबरीमला मामले को लेकर लगातार जारी हिंसा के बीच कोझिकोड जिले में मंगलवार तड़के माकपा और बीजेपी कार्यतकर्ताओं के घरों पर देशी बम फेंके गए. पुलिस ने बताया कि कोयिलान्डी इलाके में पहला बम माकपा के समिति सदस्य शिजू के घर पर फेंका गया. इसके बाद बीजेपी नेता वी के मुकुंदन के घर पर देशी बम फेंका गया. बीजेपी नेता और माकपा नेता के घरों पर हुए हमले में फिलहाल किसी भी शख्स के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. कोयिलान्डी में सोमवार को भी एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर देशी बम फेंका गया था. वहीं कन्नूर से 18 देसी बम बरामद किए गए थे. केरल में दो रजस्वला महिलाओं कनकदुर्गा (44) और बिंदू (42) के गत बुधवार को सबरीमला स्थित अयप्पा मंदिर में प्रवेश करने के बाद से ही हिंसा जारी है. ।

इसके अगले दिन ही कई हिंदू संगठनों ने बंद भी बुलाया था. पुलिस के अनुसार इस सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा में 2,187 मामले दर्ज किए गए हैं

और 6,914 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.।

बता दें गिरफ्तार किए गए लोगों में से 487 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि 2,795 लोगों को जमानत दे दी गई है. वहीं कुन्नूर में 169 और पलक्कड़ में 166 मामले दर्ज किए गए हैं. जिनमें कुन्नूर में पुलिस ने 230 लोगों को और पुलक्कड़ में 298 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

डेटा प्रोटेक्शन बिलः सोशल मीडिया में अब होंगी आपकी जानकारी सुरक्षित

नई दिल्ली ।

भारत सरकार जल्द ही सोशल मीडिया में निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल,2018 ला रही है। उम्मीद है कि सरकार अगले महीने बजट सेशन में इस बिल को संसद में पेश करेगी। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आप चिंतित हैं कि कोई अंजान व्यक्ति या कंपनी आपकी निजी जानकारियों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकती है तो आप लोगों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर सरकार नया कानून लाने जा रही है। 1) यह बिल निजी डेटा की व्याख्या करता है। निजी डेटा में व्यक्ति से जुड़ी शामिल हैं जिससे व्यक्ति की पहचान हो सकती है जैसे नाम, लिंग, जाति, पैन और आधार नंबर, पता और लोकेशन आदि। कुछ डेटा को सेंसिटिव पर्सनल डेटा के दायरे में डाला गया है जैसे व्यक्ति की यौन रूचि, राजनीतिक दल के प्रति झुकाव, आर्थिक लेन-देन और धार्मिक रूचि। व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नया फोन लेते समय या फिर सरकार की वेलफेयर स्कीम में शामिल होने के लिए निजी डेटा शेयर करता है। 2) यह बिल डेटा इस्तेमाल करने वाली फिड्यूशियरीज़ मतलब सरकारी या निजी संस्थाओं की ज़िम्मेदारी तय करता है । निजी जानकारी लेते समय व्यक्ति से सहमति लेनी होगी कि इसका इस्तेमाल किसी खास उद्देशय के लिए किया जायेगा और ज़रूरत हुई तो इसे दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा।

संस्था उतनी ही जानकारी इकठी करेगी जितनी की ज़रुरत है और उदेशय के पूरा होने तक ही जानकारी सहेज सकती है। व्यक्तिगत डेटा की दूसरी कॉपी भारत की सीमा के अंदर ही रखनी होगी। इस क़ानून में संस्था को इन शर्तों में छूट दी है अगर संस्था निजी डेटा का इस्तेमाल 3) यह बिल निजी डेटा के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली की व्यवस्था भी करता है। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (ष्ठक्रक्र) इस व्यवस्था पर नियम कानून बनाएगी। यह अथॉरिटी फिड्यूशियरीज़ या संस्था पर नजर रखेगा और।

अगर कोई संस्था कानून का उलंघ्घन करेगी तो यह अथॉरिटी उसकी जांच करेगी और उसे दंड भी देगी। कानून का उलंघ्घन करने पर संस्था को अथॉरिटी को 3 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना होगा और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

हाल ही में फेसबुक ने क़बूल किया है की उसने लगभग 9 करोड़ फेसबुक यूज़र्स जिसमें 5 लाख भारतीयों की निजी जानकारी कैंब्रिज एनालिटिका नाम की संस्था से शेयर की थी।

संपादकीय

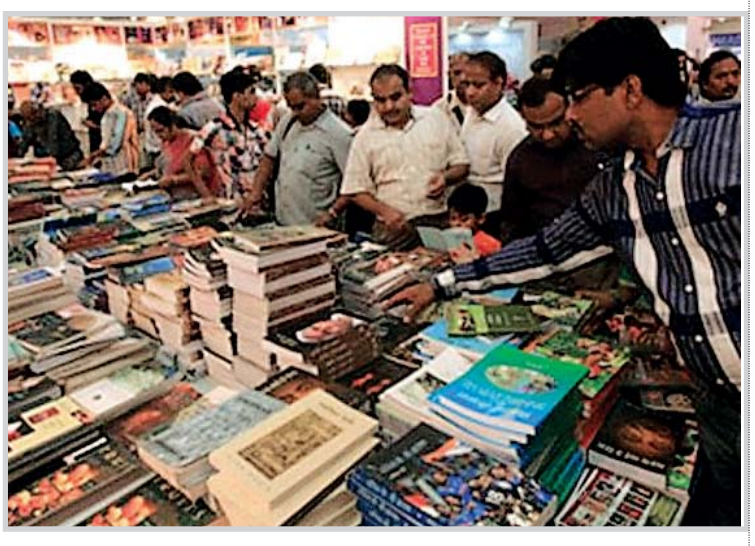

आजादी के पहले जब देश की बड़ी आबादी निरक्षर थी, तब पुस्तकों की 25-25 हजार प्रतियां छपती थीं, जबकि अब पहले संस्करण में 250 से एक हजार पुस्तकें ही छपती हैं। यह आंकड़ा साबित करता है कि हमारी पढ़ने की रुचि कम हो रही है। दिल्ली में हर साल आयोजित होने वाला पुस्तक मेला पठन-पाठन की भावना को जागृत करने का काम करता है, मगर उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है।

विकसित की जाए पुस्तक संस्कृति

हर साल की तरह इस बार भी भारत पुस्तक न्यास द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला जारी है। मेले की मुख्य थीम दिव्यांगजनों की पठन आवश्यकताएं हैं। मेले की थीम ऐसे विषय पर रखी जाती है, जिससे समाज में जागरूकता आए। इससे पहले पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और भारत की सांस्कृतिक विरासत जैसे थीम विषय रहे हैं। मेले में अमेरिका समेत 20 देश और यूनेस्को जैसी कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भाग ले रही हैं। करीब 800 प्रकाशक हिस्सा बने हैं। बावजूद इसके हिंदी पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक किस तरह पहुंचाया जाए, यह प्रश्न अपनी जगह मौजूद रहेगा। दरअसल बड़ी संख्या में हिंदी भाषी होने के बावजूद अधिकांश में पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं है। इस दृष्टि से पुस्तक पाठक तक पहुंचाने व पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। हालांकि बदलते परिवेश में जहां ऑनलाइन माध्यम पुस्तक को पाठक के संज्ञान में लाने में सफल हुए हैं, वहीं ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ी है। इसके इतर गीता प्रेस गोरखपुर ने दावा किया है कि उनकी प्रत्येक दिन 61 हजार पुस्तकें बिकती हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के खरीदारों की कमी नहीं है, बशर्ते पुस्तकें धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हों। यही वजह है कि इस समय देश में पौराणिक विषयों पर लिखी पुस्तकों की बिक्री में तेजी आई हुई है।

पुस्तक मेले का उद्देश्य जहां विविध विषयों की पुस्तकों को बिक्री के लिए एक जगह लाना है, वहीं पाठकों में पठनीयता भी विकसित करना है। इसीलिए पुस्तक जगत से जुड़ी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाएं और प्रकाशक संघ पिछले 62 साल से सक्रिय हैं। पठनीयता को बढ़ावा मिले, इसी दृष्टि से मेले में बढ़ी संख्या में पुस्तकों का विमोचन और विचार-गोष्ठियों का भी आयोजन होता है। इन आकर्षणों के बाद भी साहित्यिक पुस्तकों की बिक्री उतनी नहीं हो रही है, जितनी अपेक्षित है। इसलिए पूरा पुस्तक व्यवसाय सरकारी थोक व फुटकर खरीद पर टिका है। इस कारण पुस्तकों का मूल्य भी उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। लिहाजा सामाजिक बदलाव व संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें हमारी मित्र नहीं बन पा रही हैं। जबकि पुस्तकें ज्ञान-विज्ञान, इतिहास-पुरातत्व तथा संस्कृति व सभ्यता से जुड़ी होने के साथ पूर्व पीढ़ियों के अनुभव व उनके क्रियाकलापों से भी जुड़ी होती हैं।

साहित्य के पठन-पाठन का कारण अवमूल्यन और अराजकता बन रहे हैं। इधर तकनीकि पढ़ाई और दैनिक जीवन में उसके बढ़ते प्रभाव ने भी मनुष्य की संवेदनशीलता का क्षरण किया है। इसलिए जरूरत है कि पुस्तकें सरकारी खरीद से बाहर निकलें। पुस्तकों के विस्तार के लिए निरक्षर लोगों को साक्षर करना भी जरूरी है। साक्षरता के तमाम अभियान चलाने के बावजूद बामुश्किल 70 प्रतिशत आबादी ही साक्षर हो पाई है। हालांकि आजादी के पहले जब देश की बड़ी आबादी निरक्षर थी, तब पुस्तकों की 25-25 हजार प्रतियां छपती थीं, जबकि अब पहले संस्करण में 250 से एक हजार पुस्तकें ही छपती हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पाठक संख्या सीमित हो रही है। ऐसा टीवी चैनलों पर धारावाहिकों का सिलसिला 24 घंटे चलने और सोशल मीडिया के हस्तक्षेप से भी हुआ है। इनमें ज्यादातर ऐसी सामग्री है जो कि समाज को कुंठित और हृदयहीन बना रही है। शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी प्रभाव के चलते भी अब हिंदी पुस्तकों की बिक्री प्रभावित हो रही है। हिंदी का प्रश्न राष्ट्रीयता से जुड़ा है, इसलिए इसे सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। समाज को पुस्तकें पाठक तक पहुंचाने के लिए निजी स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। इस लिहाज से बेहद जरूरी है कि जन्मदिन, शादी समारोह और अन्य मांगलिक अवसरों पर लोग पुस्तकें भेंट करने का सिलसिला शुरू करें। इस दृष्टि से गायत्री परिवार के सदस्यों ने शादी-समारोहों में पुस्तकों के स्टाल लगाना शुरू कर दिए हैं।

हिंदी पुस्तकों की स्थिति प्रकाशकों की उदासीनता के चलते भी निराशाजक रही है। ज्यादातर प्रकाशक पाठक तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका भरोसा बड़े सरकारी संस्थानों की खरीद पर ही टिका है। इस कारण संसधानों में सेवारत विद्वान और अधिकारियों की पसंद की पुस्तकें छापने में भी प्रकाशक दिलचस्पी लेते हैं। किंतु ये पुस्तकें रुचिकर नहीं होती हैं। इसके उलट बांग्ला, मराठी और गुजराती भाषाओं की स्थिति आज भी हिंदी से बेहतर है। इन भाषाओं में पहला संस्करण पांच हजार की संख्या में छपे जा रहे हैं। हालांकि अंग्रेजी के अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के हिंदी में आने के बाद स्थिति बदली है। इन प्रकाशकों ने साहित्य की गंभीर पुस्तकों के अलावा लोकप्रिय साहित्य भी छापने का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही अंग्रेजी के लोकप्रिय भारतीय साहित्य के हिंदी अनुवादों का प्रकाशन किया है। मिथक माने जानी वाली पौराणिक साहित्यिक कृतियों को ये प्रकाशक खूब छाप रहे हैं। इनकी बिक्री भी खूब हो रही है। यह वही पुराण और इतिहास से जुड़ा साहित्य है, जो आचार्य चतुरसेन शास्त्री, गुरुदत्त, डॉ वृंदावन लाल वर्मा, नरेंद्र कोहली, रामकुमार भ्रमर और मदनमोहन शर्मा 'शाही', मनु शर्मा ने लिखा है। इस कालजयी साहित्य को वामपंथियों ने स्वीकारने के बजाय नकारने का काम किया। इस कुटिल मानसिकता के चलते हिंदी के कई नामी प्रकाशक केवल वामपंथ से जुड़ा नीरस और अपठनीय साहित्य छापते रहे। जबकि विदेशी प्रकाशकों ने इन्हीं पौराणिक किरदारों पर देवदत्त पटनायक, अमीष त्रिपाठी, चेतन भगत, आनंद नीलकंठ, प्रमोद भार्गव व अशोक बैंकर की किताबों को छापा और कई-कई संस्करण बेचे।

इनका अनुकरण करते हुए हिंदी प्रकाशकों को बुद्धि आई और उन्होंने भी तमाम लेखकों की पुस्तको के पेपरबैक संस्करण निकाले। इन किताबों में मदनमोहन शर्मा 'शाही' की 'लंकेश्वर' महंगी होने के बावजूद खूब बिक रही है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, वेस्टलैंड पुस्तक के सुदंर कलेवर के साथ विक्रय की प्रचार संबंधी रणनीतियों के चलते ज्यादा से ज्यादा पाठकों को आकर्षित कर रहे हैं। लोकप्रिय लेखन और उसे पाठक तक पहुंचाने का फायदा यह है कि बाद में पाठक गंभीर साहित्य पढ़ने में भी रुचि लेने लगते हैं। 80 के दशक तक हिंदी में ऐसा ही था। गुलशन नंदा, कुशवाहा कांत, रेणु और भ्रमर की लोकप्रिय पुस्तकों की लत पाठक को लग जाती थी, तो फिर वह प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवतीचरण वर्मा, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर आदि साहित्यकारों को भी पढ़ने लगते थे। हाल ही में एक समाचार एजेंसी की सुखद खबर आई है कि हिंदी पुस्तकों की मांग ऑनलाइन भी खूब बढ़ रही है। अभी तक इस संदर्भ में अंग्रेजी पुस्तकों का ही बोलबाला था। यह शायद पहला अवसर है जब हिंदी पुस्तकों की ई-खरीद में बढ़त दर्ज की गई है। पिछले छह माह में यह वृद्धि 60 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे ज्ञात होता है कि अंग्रेजी के वर्चस्व और प्रौद्योगिकी के बीच भी हिंदी फल-फूल रही है।

कहना नहीं होगा कि हिंदी के वास्तविक हित चिंतकों के लिए यह खबर सुखद आश्चर्य के साथ गौरवांवित करने वाली भी है। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिप कार्ड के जरिए खूब हिंदी पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। 2014 में ऑनलाइन हिंदी बुक स्टोर की स्थापना करने वाले अमेजन का दावा है कि यह मांग आगे भी और बढ़ने वाली है। ज्ञातव्य है कि शिक्षा से लेकर कैरियर के हर क्षेत्र में अंग्रेजी के बोलबाले के बीच हिंदी पुस्तकों की यह मांग उसकी प्रासंगिकता व महत्व को रेखांकित करती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि पाठकों की रुचि और जरूरतों के अनुसार पुस्तकें हिंदी में आएं तो पुस्तकों की बिक्री सुनिश्चित है। गोया, यह जरूरी है कि पौराणिक चरित्र नए-नए रूपों व संदर्भों में सामने आते रहें। पुस्तक मेले, ऐसे साहित्य के प्रचार-प्रसार और बिक्री में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।

प्रमोद भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

फर्जी लाइसेंस पर लगाम जरूरी

केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था बेहद प्रभावी सिद्ध होगी क्योंकि परिवहन विभाग में दलालों की जो भूमिका है, उसे देखते हुए यह तय कर पाना कठिन है कि वाहन चालकों को मिला लाइसेंस वैध है या नहीं।

सभी सरकारी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़े जाने के बाद सालों से चली आ रही धांधली पर सरकार लगाम लगाने में कुछ हद तक सफल रही है। इसी क्रम में सरकार ने देशभर के 6.7 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की थी। इस जांच में 16.72 लाख ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ दिनों पहले सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस संभावित रूप से फर्जी हैं। इस मामले के बाद केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने की योजना बनाई थी। इतना ही नहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए बहुत ही जल्द राज्यों के साथ नकली ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी साझा की जाएगी। अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस-आधार लिंकिंग को अनिवार्य बना सकती है। याानी इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की अनिवार्यता के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने का फैसला इस मायने में सही है कि अभी दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कोई भाग जाता है और फिर दूसरा लाइसेंस भी बना लेता है। इससे वह बच निकलता है। लेकिन आधार लिंकिंग के बाद वह अपना नाम तो बदल सकेगा, मगर बायोमीट्रिक्स नहीं। पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकते हैं। आप जैसे ही दूसरे लाइसेंस के लिए जाएंगे, सिस्टम बताएगा कि इस व्यक्ति का पहले से लाइसेंस है और दूसरा न दिया जाए और आगे की जांच में उसका दोष भी सामने आ जाएगा। अभी देखा जाए तो भारत में सड़क हादसों को तमाम प्रयासों के बाद भी रोका नहीं जा सका है और मरने वालों का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें से डेढ़ लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक, हर घंटे में दुर्घटना के 53 मामले सामने आते हैं और उनमें से 17 लोग मर जाते हैं। साल दर साल ये आंकड़े बढ़ ही रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोगों पर खतरा सबसे ज्यादा है। सड़क दुर्घटना में मरने वाले 35 फीसदी लोग दोपहिया वाहन पर ही थे। ऐसे में यह जरूरी है कि दुर्घटना के बाद दोषी व्यक्ति पर लगाम कसी जाए। यह तभी होगा जब वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सरकार और प्रशासन की नजर में हो। माना कि सड़क हादसों के लिए वजह चाहे जो हो, मगर यह व्यवस्था तो करनी ही होगी कि वाहन चालक अप्रशिक्षित न हो और उसने फर्जी तरीके से लाइसेंस न हासिल किया हो। परिवहन विभाग में आज जिस तरह से दलालों का बोलबाला है, उसे देखते हुए विभाग स्तर पर तो यह तय करना मुश्किल है कि लाइसेंस सही तरीके से बना है। फिर एक ही जरिया बनता है और वह है आधार कार्ड।

सांसद निधि पर हो सख्त फैसला

सांसदों की नीरसता के चलते सांसद निधि के फंड का इस्तेमाल न होना बेहद चिंता का विषय है। क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक संसद सदस्य को करोड़ों की राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाती है, लेकिन अब खबर यह है कि अब ज्यादातर सदस्य उस धनराशि का प्रयोग ही नहीं कर पर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर सांसदों ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल तक नहीं किया। लोकसभा के 543 सांसदों में से मात्र 35 सांसद ही अपनी विकास निधि का उपयोग कर पाए, अन्य 508 सांसदों ने विकास कार्यों में उदासीनता ही दिखाई। यह स्थिति तब है, जब देश की जनता बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पसंद के जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो सके।

देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को जिस उम्मीद के साथ संसद में पहुंचाती है, अगर उस पर नेता खरे न उतरें, तो यह न सिर्फ जनता बल्कि देश के साथ भी धोखा होगा। सांसद निधि को लेकर हमारे सांसदों की जो मनोदशा है, वह बताती है कि वे विकास के प्रति किस कदर लापरवाह हैं। लेकिन अब इस निधि पर कोई फैसला लेना होगा, ताकि विकास अवरुद्ध न हो और सांसद निधि खर्च न करने वाले सांसदों पर जुर्माना लगे।

सांख्यिकी रिपोर्ट के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद सिर्फ शान और शौकत दिखाने के लिए ही सांसद बनते हैं। जीतने के बाद उनको क्षेत्र और जनता से कोई लेना-देना नहीं होता। ऐसे सांसदों पर भविष्य में चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो नेता किसी काम का न हो उसे चुनने का क्या मतलब? इस बार कई सांसद ऐसे रहे हैं, जो अपने क्षेत्रों में एकाध बार ही गए। इनमें रंगमंच की दुनिया से जुड़े सांसदों की तादात कहीं ज्यादा है। दरअसल उनके पास अपने फील्ड का ही काम इतना होता है जिससे वह नेतागिरी में ज्यादा समय नहीं दे पाते। इस लिहाज से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे सांसद निधि को खर्च करने में समय कैसे निकालेंगे। दरअसल ऐसे व्यक्तियों को संसद में भेजने का क्या फायदा जो इलाके का विकास ही न कर सके। जो सांसद धन होने के बाद भी नीरसता दिखाए उसे घोर लापरवाही ही कहेंगे। ऐसे व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ और शौक के लिए ही सांसद बनते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को सचेत रहने की जरूरत है। जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा, जो अपने क्षेत्र और देश के प्रति विकास की अवधारणा साबित कर सकें।

सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार में ऐसे सांसदों की एक लिस्ट तैयार हुई है जिसे सार्वजनिक की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के ऐसे सांसदों के टिकट भी काटने की तैयारी में हैं। दूसरे सियासी दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। स्कूलों में जब कोई छात्र कम उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है तो ठीक उसी तर्ज पर सांसदों की भी चुनाव लड़ने से बेदखली का कोई प्रावधान होना चाहिए। जनता के धन का दोहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे गुनाह की श्रेणी में लाना चाहिए। सरकार के लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की यह रिपोर्ट चिंतित करने जैसी है। इस रिपोर्ट के बाद गहन मनन-मंथन भी किया जा रहा ह, लेकिन समाज में संदेश बहुत गलत जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को अपने पूरे कार्यकाल में 21 हजार 125 करोड़ रुपए सांसद निधि के तौर पर खर्च करने के लिए आवंटित किए जाते हैं।

पिछले दस सालों से देखने को मिला है कि यह राशि खत्म नहीं हो सकी। कुल राशि में करीब 12 हजार करोड़ रुपए अभी तक सरकारी सुस्ती के कारण सरकारी खजाने में सुरक्षित हैं। इस राशि को खर्च करने की सांसदों ने पहल ही नहीं की है। इस मसले पर हाल में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्यवयन मंत्रालय ने इस साल की सालाना समीक्षा बैठक कर गहरी चिंता जताई है। गौरतलब है कि वर्ष 1993 में जब प्रथमतः सांसद निधि का प्रावधान लागू किया गया था। तब भी विरोध हुआ था। उस वक्त यह तक कहा गया था कि इससे भ्रष्टाचार में तब्दीली आएगी। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार समिति इस फंड को समाप्त करने की सिफारिश भी कर चुकी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसद निधि की राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए सालाना कर दिया था। जिस सांसद निधि को पीवी नरसिम्हा राव ने एक करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी ने दो करोड़ और डॉ. मनमोहन सिंह ने पांच करोड़ किया, उसी सांसद निधि के लिए कई सांसद मांग कर रहे हैं कि अब यह राशि पचास करोड़ रुपए कर दी जाना चाहिए, ताकि सांसद आदर्श-ग्राम योजना का क्रियान्वयन किंचित सुविधाजनक हो सके।

सवाल उठता है जब मौजूदा फंड ही खर्च नहीं होता है, तो फिर बढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता है। दरकार इस बात की है कि इस फंड को सीधे अब केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिए, जिस सांसद को जितना पैसा चाहिए उसे मांगपत्र के आधार पर ही मुहैया किया जाए। हालांकि सांसदों की राशि बढ़ाए जाने की मांग को फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकार दिया है। साथ ही फंड का इस्तेमाल न करने वाले सांसदों की समीक्षा करने का प्लान तैयार किया है। ऐसा किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जनता के नाम से आवंटित होने वाला धन जब उन तक पहुंचेगा ही नहीं तो भला उनका विकास कैसे होगा। पिछले दो दशकों से घोटालों के लिए कुख्यात हो चुकी सांसद निधि ने राजनीति और लोकतंत्र के विश्वास को दागदार कर दिया है। इसे नियंत्रित करना शायद अब किसी के लिए संभव नहीं रहा। इस फंड को खत्म करना ही मात्र विकल्प हो सकता है।

अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के प्रश्नकाल में सांसदी फंड पर भी चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर सांसद इस जंजाल में फंसे थे तो ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया इस मसले को। लेकिन यह विषय बहुत ही चिंतित करने वाला है। जनता को अब अपने सांसदों के संबंध में पूरा ब्योरा रखना ही चाहिए और जब वे मिलें तो उनसे अपने मौलिक सवाल भी करने चाहिए। लोकसभा में कुल 545 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के तहत सांसद को पांच करोड़ रुपए की सालाना दो किस्तें मिलती हैं। लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल पांच साल का होता है जबकि राज्यसभा का छह साल का होता है। इन सबों का खाका सबके पास होना चाहिए। पिछले दस सालों में देखने को मिला है कि कई सांसदों ने अपनी आवंटित राशि खत्म नहीं की। करीब 12 हजार करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनको सांसदों ने खर्च नहीं किया। यह पैसा जनता का है जो उन तक पहुंच ही नहीं सका। इसके पूर्णतः जिम्मेदार वह नाकाबिल सांसद हैं जिन्हें जनता ने बड़ी उम्मीदों से सदन में भेजा।

हालांकि केंद्र सरकार पिछले सप्ताह से ही सांसदों और राज्य सरकारों पर इस रकम को जल्द जल्द खर्च करने का दबाव बना रही है। ताकि 2019 चुनावों से पहले विकास कार्यों का फायदा देश के गरीब और जरूरतमंदों को हासिल हो सके। लोकसभा के सांसदों को कुल 13 हजार 625 करोड़ रुपए और राज्यसभा के सांसदों को कुल 7500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ऐसे में सांसद निधि के तहत विकास योजनाएं के लिए कुल 21 हजार 125 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जिनके जरिए विकास के जरूरी काम किए जाने थे। सभी कागजी साबित हुए। फंड का इस्तेमाल न करने वाले सांसदों को उनकी पार्टी की ओर से एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उनको हिदायतें भी दी जाने चाहिए।

सांसद निधि की यह असलियत पिछले कई वर्षों से सामने आ रही है। लेकिन अब इस निधि पर कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा, ताकि सिर्फ सोच के चलते देश के विकास पर बट्टा न लगे और सांसद निधि खर्च न करने वाले सांसदों पर जुर्माना लगे।

रमेश ठाकुर
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

हम ऑनलाइन प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं जहां लाइसेंस हासिल करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड टेस्ट किया जाएगा। सभी को परीक्षा देनी होगी, चाहे वह कोई हो।

नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना जनता के हित में होगा। अब लोग दुर्घटना करने के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा और न ही नया लाइसेंस बनवा सकेगा।

रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री

सत्यार्थ

चालाक सभासद

राजा यशकीर्ति भेष बदलकर हर रात्रि को भ्रमण करने निकलते थे। एक बार एक गांव में उन्होंने देखा कि कुछ युवक एक खेल, खेल रहे हैं। एक युवक राजा बना बैठा था। शेष सभासद के रूप में थे। युवक बोला- सभासदो, जिस राज्य के कर्मचारी सदैव वैभव-विलास में ही डूबे रहते हों, उसका राजा कितना ही नेक व प्रजावत्सल क्यों न हो, प्रजा सुखी नहीं रह सकती। यशकीर्ति के राज्याधिकारी जो भूल कर रहे हैं, वह तुम मत करना। यशकीर्ति उस युवक के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उसे अपने साथ ले आए व अपना महामंत्री बना लिया। सुकेश नामक वह युवक लकड़हारा था। वह अपने साथ एक कुल्हाड़ी, बिछौना और अंगोछा भी लाया था। इस नए महामंत्री ने समस्त मंत्रियों, सामंतों व कर्मचारियों के लिए एक सख्त आचार-संहिता बनाई। अब सभी को 10 घंटे काम नित्य करना पड़ता था। राजकोष का धन प्रजा की भलाई में लगने लगा। कुछ सभासद सुकेश के पीछे पड़ गए। उन्होंने पता लगाया कि उसे जो आवास मिला है, वहां एक कक्ष है, जहां और कोई नहीं जा सकता। राजा से शिकायत की कि उसने काफी धन वहां छिपा रखा है। राजा ने महामंत्री के आवास का दौरा किया। सुकेश ने स्वयं उस कक्ष को खोला और राजा को प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। वहां कुल्हाड़ी, बिछौना और अंगोछा रखे हुए थे। उसने ये सभी चीजें उठाईं और यह कहते हुए चल दिया-बस, अब मेरा यहां कोई काम नहीं। यशकीर्ति अपने सभासदों के षड्यंत्र के चलते हाथ मलते रह गए। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के कहे पर आंख मूंदकर यकीन करता है, उसे बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए जो भी काम करें, स्वविवेक से करें।

सुभाष बुड़ावनवाला

उड़ान-1 के 44 फीसदी रूटों का आवंटन रद्द

नई दिल्ली।

मोदी सरकार की 'हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सफर कराने' के उद्देश्य से छोटे तथा मझौले शहरों के लिए शुरू की गयी किफायती विमान/हेलिकॉप्टर सेवा योजना 'उड़ान' के पहले चरण में आवंटित 44 प्रतिशत मार्गों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। उड़ान के पहले चरण के तहत 128 रूटों का आवंटन किया गया था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इनमें 56 रूटों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। इनमें वे रूट शामिल हैं जिन पर आवंटी कंपनी या तो सेवा शुरू ही नहीं कर सकी या सेवा शुरू तो की, लेकिन उसकी 30 प्रतिशत से ज्यादा उड़ानें रद्द रहीं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एयर ओडिशा को आवंटित 40 रूट और एयर डेक्कन को आवंटित 16 रूटों पर उड़ानें रद्द की गयी हैं। एयर ओडिशा को 50 और एयर डेक्कन को 34 मार्गों का आवंटन किया गया था। इनके अलावा टूजेट को 18, एयर इंडिया की इकाई अलायंस एयर को 15 और स्पाइसजेट को 11 मार्गों का आवंटन हुआ है। इन मार्गों का आवंटन 30 मार्च 2017 को किया गया था और हवाई अड्डा तैयार होने के छह महीने के भीतर कंपनी को सेवा शुरू करनी थी। 'उड़ान' या क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत दूरी के हिसाब से हर मार्ग का अधिकतम किराया तय कर दिया गया है। हर उड़ान में आधी सीटें योजना के तहत बुक की जाती है जबकि शेष सीटों की बुकिंग कंपनी बाजार मूल्य के हिसाब से कर सकती है। अधिकतम किराया तय होने से विमान सेवा कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरसीएस कोष से उसे पैसा दिया जाता है।

प्रति सीट न्यूनतम क्षतिपूर्ति मांगने वाली कंपनी को मार्ग का आवंटन किया गया है। उड़ान के दूसरे चरण में भी रूटों का आवंटन 24 जनवरी 2018 को किया जा चुका है। इसमें 325 रूटों का आवंटन किया गया था।

दिल्ली में सस्ते में घर खरीदने का मौका, डीडीए बेचेगा 21,000 फ्लैट्स

नई दिल्ली।

डीडीए इस साल दो हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इस दोनों स्कीमों में सिर्फ नए फ्लैट्स होंगे। ये फ्लैट्स तैयार हो चुके हैं इनमें सिर्फ पानी का कनेक्शन लेना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डीडीए के पास करीब 15 हजार फ्लैट्स तैयार हैं। पहली स्कीम मार्च-अप्रैल तक लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें 10 हजार फ्लैट्स होंगे। साल के अंत में दूसरी स्कीम में करीब 11 हजार फ्लैट्स होंगे। इन स्कीम में सभी कैटेगरी के फ्लैट्स शामिल होंगे। इनमें भी सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स होंगे। इन फ्लैट्स की संख्या करीब 40 से 50 फीसदी होगी। इन फ्लैट्स के साइज की बात करें तो यह पिछली दो स्कीमों के फ्लैट्स साइज से बड़ा है। इसे लेकर उपभोक्ताओं को छोटे साइज की समस्या नहीं आएगी। इन दो स्कीमों के तहत मिलने वाली फ्लैट्स अधिकतर रोहिणी, नरेला में हैं। डीडीए इन जगहों के आसपास मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्कूल के लिए प्लॉट देने की तैयारी भी कर रहा है। डीडीएम के नए फ्लैट्स की इस स्कीम का लोगों को काफी इंतजार है। करीब 6 साल बाद बड़े साइज के फ्लैट्स की स्कीम आ रही है। डीडीएम ने 2018 में 21 हजार

फ्लैट्स की स्कीम लाने का दावा किया था लेकिन स्कीम नहीं ला पाई। इसके बाद अब इस साल दो स्कीम लाकर भरपाई करने की कोशिश की जा रही है।

भारत ने ईरान के बैंक को मुंबई में शाखा खोलने की मंजूरी दी

नई दिल्ली।

सरकार ने ईरान के एक बैंक को मुंबई में अपनी शाखा स्थापित करने की स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत यात्रा पर आए ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ राजधानी में मंगलवार को बैठक के बाद यह जानकारी दी। ईरान का बैंक पसरगाद अगले तीन महीने में यह शाखा चालू करेगा। गडकरी ने बताया कि सरकार इसकी अनुमति पहले ही दे चुकी है। ईरानी बैंक तीन माह में मुंबई में शाखा चालू कर देगा। इससे पहले गड़करी ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। गडकरी के पास जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे विभागों की जिम्मेदारी है। बैठक के बाद उन्होंने कहा, ''हमने विस्तार से बाचतीत की है हमारी यह बैठक बड़ी सार्थक रही और हमने बहुत से मुद्दों का समाधान कर लिया है।'' भारत ने इस बंदरगाह के लिए 8.5 करोड़ डॉलर की मशीनों की खरीद का आर्डर जारी कर रखा है। यह बंदरगाह दक्षिणी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर है। गडकरी ने कहा, ''ईरान के मंत्री के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। चाबहार पर माल आना शुरू हो गया है और पहला जहाज ब्राजील से माल लेकर आया। वहां परिचालन के लिए वित्त का प्रबंध पूरा किया जा चुका है। कुछ दिक्कतें थीं पर हमने इन मुद्दों का समाधान कर लिया है।'' उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच वस्तु व्यापार व्यवस्था अपनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। गडकरी ने यह भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री ने कई प्रस्ताव सुझाए हैं।

सरकार ने उर्वरक निर्यात के नियमों में ढील दी

नई दिल्ली।

सरकार ने सोमवार को यूरिया, पोटाशिक और फॉस्फेट सहित उर्वरकों के निर्यात के नियमों को उदार कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में कहा गया है कि उर्वरकों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। 'अंकुश' वाली श्रेणी के उत्पादों को 'मुक्त' श्रेणी में डाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन निर्यात के लिए विनिर्माताओ-निर्यातकों को उर्वरक विभाग से पहले अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। भारत हालांकि, इन उर्वरकों फॉस्फेटिक और पोटाशिक और यूरिया का शुद्ध आयातक है। यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत एकमात्र उर्वरक है।

सीधे कृषि में इस्तेमाल के लिए इसका आयात सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार उपक्रमों (एसटीई) एमएमटीसी, एसटीसी के जरिए सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में नवंबर माह तक भारत ने 104.85 करोड़ डॉलर के 42.03 लाख टन यूरिया का आयात किया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान यूरिया का आयात 59.75 लाख टन रहा था। मूल्य के हिसाब से यह 129.57 करोड़ डॉलर रहा था। वर्ष 2016- 17 में 54.81 लाख टन यूरिया का 104.72 करोड़ डॉलर में आयात किया गया। इसी प्रकार 2017- 18 में देश में डीएपी का 42.17 लाख टन आयात किया गया। एनपीके का 4.99 लाख टन और एओपी का 47.36 लाख टन आयात किया गया।

स्थिर रहे पेट्रोल के रेट, डीजल के दाम में मामूली कटौती

बिजनेस डेस्क। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज गिरावट दिखाई दी। नए साल में पहली बार कल पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है। आईओसीएल की वेबसाइट के अनुसार, तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 21 पैसे और डीजल की कीमतों में 8 पैसे की बढ़ोतरी की थी। हालांकि दो दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस साल एक जनवरी को पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे की कटौती हुई थी। दो और तीन जनवरी को कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन चार जनवरी को 21 पैसे और फिर 5 जनवरी को 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ। इसके बाद 6 जनवरी को कीमतों स्थिर रहीं, जबकि सोमवार सात जनवरी को कीमतें पहली बार बढ़ी हैं और आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ जब्कि डीजल के दाम में मामूली कटौती हुई। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 68.50 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में यह 74.16 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में 70.64 रुपए प्रति लीटर, और चेन्नई में पेट्रोल 71.07 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

बाजार में नकद-धन की दिक्कत होने पर कदम उठाए जाएंगे: रिजर्व बैंक के गवर्नर

बिजनेस डेस्क।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि कर्ज देने के लिए बैंकों की नकद धन की आवश्यकताओं को फिलहाल पूरा किया जा चुका है और यदि अर्थव्यवस्था में तरलता की दिक्कत हुई तो केंद्रीय बैंक आवश्यक और कदम उठाएगा। गवर्नर दास ने राजधानी में सोमवार को छोटे एवं मझोले उपक्रमों के संघों के साथ बैठक की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार को मुंबई में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ उनकी स्थिति पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र के वसूली में अटके ऋणों के पुनर्गठन के व्यक्तिगत प्रस्तावों पर गौर करते समय संबंधित इकाई के कारोबार की मजबूती को ध्यान में रखने को कहा गया है।दास ने तरलता पर कहा, ''हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि कुल मिला कर तरलता (धन) की जरूरतें पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि तरलता की दिक्कतें हुई तो रिजर्व बैंक कदम उठाएगा। उन्होंने पर्याप्त तरलता बनाये रखने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से ही तरलता की मात्रा बढ़ायी जाएगी। एमएसएमई के साथ बैठक के बारे में दास ने कहा कि बैंकों को ऋण के पुनर्गठन से पहले एमएसएमई की वहनीयता परखने के लिये कहा गया है।

नई ई-कामर्स नीति से घटेगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत के कारोबारियों को लगेगा झटका

बिजनेस डेस्क।

नई ई-कामर्स नीति से भारत के कारोबारियों को भारी नुक्सान झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बाजार विशेषज्ञों का भी यहीं मानना है कि विदेशी ई-कामर्स कंपनियों के लिए नियम सख्त करने से लम्बे समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनका कहना है कि नियमों में बदलाव भारतीय उपभोक्ताओं के हित में नहीं। एक तरफ भारत सरकार सौ अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने की बात करती है तो दूसरी तरफ नए नियम बना देती है, इससे विदेशी कंपनियों को गलत संदेश जाएगा। इससे निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ई-कामर्स कंपनियों के लिए बनाए गए सख्त नियमों का इस क्षेत्र पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। सरकार ने जनेस मॉडल में बदलाव करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है कंपनियों की माने तो ये बहुत कम समय है वहीं बदलावों को लेकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां सरकार का दरवाजा खटखटा सकती है और नियम लागू करने की समयसीमा को एक फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग कर सकती हैं। कंपनियों का मानना है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में जो बदलाव किए गए उनका पालन करने और उनको परिचालन में लाने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। नई नीति से एमेजान और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। घरेलू कारोबारी काफी अर्से से ई-कामर्स कंपनियों के कामकाज से नाराज हैं और सरकार से मांग कर रहे थे कि ई-कामर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए। नए नियमों का मकसद इन प्लेटफार्मों को किसी भी तरह से पक्षपात से मुक्त करना है। कलाउडटेल को ऐमेजान और डब्ल्यूएस रिटेल को फ्लिपकार्ट से जोड़कर देखा जाता है लेकिन नए नियमों की वजह से वे संबंधित प्लेटफार्म्स पर सामान नहीं बेच पाएगी। फ्लिपकार्ट की नई मालिक बालमार्ट खुद इस ई-कामर्स प्लेटफार्म पर सामान नहीं बेच पाएगी। ई-कामर्स प्लेटफार्म्स की सहयोगी इकाइयों की तरफ से डिस्काउंट को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थीं वे लाजिसस्टिक्स और होलसेल एंटिटी के जरिए ये छूट दे रहे थे। व्यापारी संगठन और छोटे व खुदरा व्यापारी सरकार के इस फैसले से खुश हैं।

ई-कामर्स कंपनियों के बंपर छूट और कैशबैक जैसे ऑफर से कई छोटे कारोबारियों का मुनाफा आधा हो गया और उनके अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

एक्सा के साथ म्यूचुअल फंड से बाहर होने की तैयारी में

नई दिल्ली। एक्सा बैंक ऑफ इंडिया के साथ म्यूचुअल फंड संयुक्त उद्यम से बाहर होने पर विचार कर रहा है। यूरोप के सबसे बड़े फंड मैनेजरों में से एक एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स बैंक ऑफ इंडिया के साथ भारतीय म्यूचुअल फंड संयुक्त उद्यम में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। फ्रांसीसी बीमा कंपनी एक्सा ग्रुप के पूंजी प्रबंधक के यूनिट की बैंक ऑफ इंडिया एक्सा म्यूचुअल फंड में 49 फीसदी हिस्सेदारी है। यह जानकारी इस मामले से संबंध रखने वाले दो लोगों ने दी। एक व्यक्ति ने कहा कि निजी इक्विटी फर्म केकेआर द्वारा नियंत्रित एवेंडस समूह ने इस हिस्सेदारी खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। मुंबई स्थित वित्तीय सेवाओं की फर्म इस फंड हाउस में अपना अधिकांश हिस्सा बनाए रखने में इच्छुक है। बैंक ऑफ इंडिया की इसमें हिस्सेदारी 51 फीसदी है। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि दबाव के तहत सरकारी बैंक अपनी हिस्सेदारी एक्सा म्यूचुअल फंड को बेचने की इच्छुक है, ताकि वह अपने असंबंध व्यवसायों से बाहर हो जाए, मगर उसे कोई खरीदार नहीं मिला। इस संबंध में जब एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और एवेंडस को ई-मेल के जरिए सवाल पूछे गए तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। उक्त व्यक्ति के अनुसार, एक्सा ने बैंक ऑफ इंडिया को अपनी हिस्सेदारी बेचने के अपने फैसले के बारे में लिखा है कि एक्सा इस संयुक्त उद्यम से बाहर होना चाहता है। ऐसी स्थिति में बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकता है ताकि नए निवेशकों को फर्म में अधिक हिसेदारी मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 2012 में इस फंड हाउस में 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। बैंक ने एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स से 26 फीसदी और टैलीकॉम कंपनी भारतीय उद्यम से 25 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी थी। इस फंड में बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी अधिक थी लेकिन एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स कारोबार करता था।

अनिल अंबानी, अडानी को गहलोत सरकार का झटका, 240 एमओयू होंगे रद्द

जयपुर।

अशोक गहलोत सरकार रिसर्जेंट राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के 200 से ज्यादा एमओयू निरस्त करेगी। पिछली भाजपा सरकार ने नवंबर 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट में 3.37 लाख करोड़ रुपए के 470 एमओयू किए थे। इसके मुताबिक इन कंपनियों को राजस्थान में पर्यटन, खनन और मेडिकल जैसे क्षेत्र में निवेश करना था। बदले में सरकार ने इन्हें जमीन और टैक्स में रियायत देने की बात कही थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस समूह और गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनियों ने एमओयू तो साइन किए लेकिन निवेश करने में ज्यादातर कंपनियों ने रुचि नहीं दिखाई। मौजूदा उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के मुताबिक पिछले तीन सालों में इनमें से सिर्फ 124 एमओयू ही ऐसे रहे जिन पर काम शुरू हुआ। इनसे सिर्फ 12 हजार करोड़ रुपए का ही निवेश आ सका है। जिन कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया है उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। कंपनियां नहीं आती हैं तो एमओयू रद्द किए जाएंगे। सबसे ज्यादा विफलता पर्यटन, खनन और मेडिकल के एमओयू में देखने को मिली। इनमें ढाई लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के करीब 240 एमओयू किए गए।

इन्हीं में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा रही। टूरिज्म में 10,442 करोड़ के 221 एमओयू और मेडिकल में करीब 2,700 करोड़ रुपए के 14 एमओयू से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। माइंस में 76 हजार करोड़ के 25 एमओयू हुए लेकिन निवेश सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का आया। कुल 470 में से 154 एमओयू पिछली सरकार में ही निरस्त माने जा चुके थे। इनके निवेशकों ने समिट के बाद फॉलोअप नहीं किया। रिन्यूएबल एनर्जी में रिलायंस एनर्जी, अडानी, एजर पावर इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों ने 1.90 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए।

रिलायंस एनर्जी, एजर पावर इंडिया, सन एडिसन ने एमओयू के बाद फोलोअप नहीं किया।

संक्षिप्त समाचार

सोना 40 रुपए महंगा ;चांदी 210 रुपए लुढ़की

बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दोनों कीमती धातुओं में रही तेज गिरावट के बीच वैवाहिक जेवराती मांग आने से दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 40 रुपए महंगा होकर 32,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान औद्योगिक ग्राहकी सुस्त पडने से चांदी भी 210 रुपए की गिरावट में 39,800 रुपए प्रति किलोग्राम बोली गयी। विदेशी बाजारों में लंदन का सोना हाजिर 6.32 डॉलर की गिरावट के साथ 1,282.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिका का मार्च सोना वायदा भी 6.90 डॉलर की गिरावट के साथ 1,283.0 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इस बीच चाँदी हाजिर भी 0.10 डॉलर फिसलकर 15.53 डॉलर प्रति औंस पर आ गयी। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया भर की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के मजबूत होने से पीली धातु पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक बातचीत होने के संकेत से भी निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश में कम रहा।

इन्फोसिस की यूनिट के ग्लोबल हेड ने कंपनी छोड़ी, 6 महीने में तीसरा बड़ा इस्तीफा

बेंगलुर। आईटी कंपनी इन्फोसिस के ग्लोबल हेड (एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज और सर्विसेज यूनिट) सुदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुदीप करीब 20 साल से इन्फोसिस के साथ जुड़े हुए थे। उनके इस्तीफे की वजह पता नहीं चल पाई है। सुदीप अपने वर्टिकल में 1.5 अरब डॉलर का पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। सुदीप ने अपने वर्टिकल का रेवेन्यू 10 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 75 करोड़ डॉलर पहुंचा दिया था। छह महीने में इन्फोसिस से यह तीसरा बड़ा इस्तीफा है। सुदीप से पहले अक्टूबर 2018 में कंपनी के कंसल्टिंग ग्लोबल हेड केन टूम्ब्स ने इस्तीफा दिया था। अगस्त 2018 में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमडी रंगनाथ ने पद छोड़ा था।

सरकार ने दी उर्वरक निर्यात के नियमों में ढील

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को यूरिया, पोटाशिक और फॉस्फेट सहित उर्वरकों के निर्यात के नियमों को उदार कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना में कहा गया है कि उर्वरकों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। 'अंकुश' वाली श्रेणी के उत्पादों को 'मुक्त' श्रेणी में डाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन निर्यात के लिए विनिर्माताओ-निर्यातकों को उर्वरक विभाग से पहले अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। भारत हालांकि, इन उर्वरकों फॉस्फेटिक और पोटाशिक और यूरिया का शुद्ध आयातक है।यूरिया सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत एकमात्र उर्वरक है। सीधे कृषि में इस्तेमाल के लिए इसका आयात सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार उपक्रमों (एसटीई) एमएमटीसी, एसटीसी के जरिए सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत किया जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में नवंबर माह तक भारत ने 104.85 करोड़ डॉलर के 42.03 लाख टन यूरिया का आयात किया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान यूरिया का आयात 59.75 लाख टन रहा था। मूल्य के हिसाब से यह 129.57 करोड़ डॉलर रहा था। वर्ष 2016- 17 में 54.81 लाख टन यूरिया का 104.72 करोड़ डालर में आयात किया गया। इसी प्रकार 2017-18 में देश में डीएपी का 42.17 लाख टन आयात किया गया। एनपीके का 4.99 लाख टन और एओपी का 47.36 लाख टन आयात किया गया।

जीडीपी की 7.2 वृद्धि दर बेहतरः सुभाष चंद्र गर्ग

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने सोमवार को कहा कि 2018-19 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान काफी अच्छा है। इसके साथ भारत दुनिया में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीन अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में देश की आर्थिक प्रगति 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 6.7 प्रतिशत थी। गर्ग ने ट्वीट श्रृंखला में कहा, ''2018-19 के लिए जीडीपी वृद्धि के नवीन अनुमान बेहद अच्छे हैं। 2017-18 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।'' उन्होंने कहा कि दुनियाभर में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढने वाली बनी रहेगी। वर्तमान बाजार कीमत पर जीडीपी 12.3 प्रतिशत बढ़कर 188.41 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़कर 1,41,447 रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। इसमें आगे कहा गया है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में वृद्धि से निवेश गतिविधियों में तेजी का संकेत मिलता है।

सूरत महानगर पालिका शहेरी गरीब कल्याण मेला 2018-19 के अंदर्गत लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की सहायता की गई। जिसमें कुल13757 लाभार्थियों को 21567.06 रुपये की सहायता दी गई। शहर के अडाजन स्थित संजीव कुमार ऑडिटोरियम में आयोजित सूरत महानगर पालिका गरीब कल्याण मेंला सामाजिक न्याय और अधिकारी ता मंत्री ईश्वर परमार के हाथों किया गया।

पिछले कई सालों में मिले मांझे के जख्म फिर होंगे ताजा

सूरत। मकर संक्रांति पर हर साल मांझे से कई दुर्घटनाएं होती है और कई परिवारों के लिए पर्व का हर्षोल्लास मातम में तब्दील हो जाता है। रोकर के बावजूद कांच मिले तेज धार वाले मांझे के इस्तेमाल से सूरत में पिछले साल सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे और कुछ को जान से हाथ धोना पड़ा था।

सूरत में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व पर पतंगबाजी के लिए एक तरह से पूरा शहर इमारतों की छत पर होता है। अब तबकि मकर संक्राति एक हफ्ते दूर है, शहर के ज्यादातर विस्तारों में पतंग और मांझे पर बाजार सज गया है। कांच की धार वाला मांझा भी चोरी-छिपे बिक रहा है। पिछले साल ऐसे मांझे से कई लोगों के गले कट गए थे, जिन्हें न्यू सिविल, स्मीमेर और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. इनमें से कुछ की मौत हो गई थी। सीमाड़ा की कृष्णापार्क सोसायटी निवासी छह वर्षीय केयर हितेश पटोलिया मकर संक्रांति की सुबह पिता हितेश पटोलिया के साथ मोटर साइकिल पर वराछा के एके रोड़ पर मंदिर दर्शन के लिए गया था।

कापोद्रा चौपाटी के पास से गुजरते हुे केयुर के गले में मांझा फंस गया। उसे पीपी सवाणी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया गया। इसी तरह उधना की विजयानगर सोसायटी निवासी तीन साल का आदित्य विजय झावरे पिता के साथ मोटर साइकिल पर उधना के क्षत्रपति मराठी स्कूल के सामने से गुजर रहा था। मांझा मोटर साइकिल के सामने आने से आदित्य के गले में फंस गया। उसे निर्मल अस्पताल में ले जाया गया जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। वराछा कारगिल चौक की शिवशक्ति सोसायटी निवासी 55 वर्षीय कांति पादरिया के गले में राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर मांझा फंस गया था। अधिक रक्त बह जाने से उसकी मौत हो गई थी।

मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब सूरत पुलिस को मिली साप्ताहिक छुट्टी

सूरत। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही किसानों की कर्ज माफी के साथ ही पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी का वादा पूरा कर दिया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब सूरत में पुलिस कर्मियों को विकली ऑफ का आदेश जारी किया गया है। सूरत पुलिस आयुक्त सतीश शर्मा ने एक परिपत्र जारी कर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का आदेश दिया है। परिपत्र में सूरत शहर के पुलिस थानों में सेवारत पीआई और पीएसआई को साप्ताहिक छुट्टी यानी रविवार को अवकाश का ऐलान किया गया है। उनके स्थान पर रविवार को सेकण्ड पीएसआई या सीनियर पीएसआई पुलिस थाने का चार्ज संभालेंगे। इसके अलावा रविवार के अतिरिक दिनों में रोटेशन के मुताबिक पुलिस थाने में काम करनेवाले पुलिसकर्मियों को भी विकली ऑफ की बात कही गई है। परिपत्र में कहा गया है कि पूरे सप्ताह काम सेवारत रहनेवाले पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। हालांकि विकली ऑफ के दिन हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकेंगे और न ही इसके साथ अन्य छुट्टियां भी नहीं जा सकेंगी।

बीआरटीएस टक्कर से मौत की २४ घंटे में दूसरी

बोपल में बीआरटीएस बस की टक्कर से दो युवकों की मौत

अहमदाबाद। बोपल उमिया माता मंदिर के पास मंगलवार को सुबह में बीआरटीएस बस और बाइक के बीच की दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी। घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। विशेष करके बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत होने से स्थानीय निवासियों में शोक की लहर फैल गई। बीआरटीएस बस के नीचे कुचल गये बाइकसवार युवकों में से एक की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल में गंभीर चोटें आयी होने की वजह से उपचार के दौरान मौत हो गई थी। दुर्घटना में एक की घटनस्थल पर मौत हो गई थी। जबकि दूसरे युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बोपल पुलिस के बताये अनुसार, घुमागाम के निवासी विपुल भाभोर (उम्र.२०) और कल्पेश आमलीया (उम्र.२०) मंगलवार को सुबह में पल्सर बाइक लेकर निकले। उमिया माता मंदिर के पास बीआरटीएस ट्रेक में तेजी से बाइक चला रहे सामने से आ रही बीआरटीएस बस के साथ बाइक टकराने से दोनों को गंभीर चोटें आई थी। जिसमें विपुल को गंभीर चोटें आयी जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि कल्पेश को गंभीर चोटें आयी होने की वजह से इसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।हालांकि गंभीर चोटें आयी होने की वजह से उपचार के दौरान मौत हो गई थी। दूसरी तरफ, घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। लोगों की भीड़ घटनास्थल लग गई और इसकी वजह से ट्राफिक चक्काजाम हो गया युवक की मौत के समाचार को लेकर विशेष करके मरने वाले युवक बोपल के घुमा गाम के निवासी होने की वजह से पूरे क्षेत्र में और घुमा गाम में शोक की लहर फैल गई। बोपल पुलिस ने पूरे मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।

प्वाइंट ब्लैंक रेंज से भानूशाली को छाती और आंख में गोली मारी गई

भाजपा के पूर्व विधायक जयंति भानूशाली की चालू ट्रेन में हत्या

हत्या की वजह से भाजपा सहित राज्यभर में सनसनी : मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गंभीर दु:ख व्यक्त करके न्यायिक जांच का आश्वासन दिया है

अहमदाबाद। अबडासा के भाजपा के पूर्व विधायक जयंति भानूशाली की गत देर रात को सयाजीनगरी एक्सप्रेस में हत्या की गई थी। वह भूज से अहमदाबाद आ रहे इस दौरान मालिया के पास अज्ञात शख्सों ने फर्स्ट क्लास एसी (एच १) कोच में घुसकर उन पर प्वाइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायरिंग करने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। भानूशाली को छाती और आंख में गोली मारी गई थी। भाजपा के पूर्व विधायक जयंति भानूशाली की चालू ट्रेन में ही हत्या की वजह से भाज पा सहित राज्यभर में सनसनी मच गई। मालिया में पोस्टमोर्टम करके शव को

अहमदाबाद सीविल अस्पताल में पोस्टमोर्टम के लिए लाया गया था। एफएसएल की टीम के डॉक्टर पोस्टमोर्टम करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। हत्या की जांच करने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीम (सीट) की रचना की गई है। हत्या की घटना में पवन मोरी नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इसे भी अहमदाबाद लाकर पूछताछ शुरू की गई है। पूर्व विधायक जयंति भानूशाली पर फायरिंग करके हत्या की घटना कटारिया-सूरजबारी स्टेशन के बीच हुई थी। जिसमें जयंतीभाई को एक गोली छाती के हिस्से में और दूसरी गोली आंख के हिस्से में लगी थी। वह सयाजीनगरी ट्रेन नंबर-१९११६ में सवार थे। घटना रात को २ बजे के करीब हुई है यह जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद रेलवे के डीवायएसपी पीपी पीरोजीया जांच कर रहे है। राज कोट के डीवायएसपी, रेलवे एलसीबी के एक पीआई और दो पीएसआई और कॉन्स्टेबल जांच करेंगे। हाल में मोरबी जिला पुलिस, रेलवे एलसीबी, जिला एलसीबी, गांधीधाम पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की गई है। इस हत्या में पुलिस द्वारा रेलवे में अभी तक हुए विभिन्न मर्डर की थियरी जांच की जाएगी।

सीआईडी और रेलवे के डीजी भाटिया का खुलासा

भानूशाली की हत्या के बाद बीच चेन पुलींग हुई

अहमदाबाद। जयंती भानूशाली की हत्या बाद गांधीधाम से सामखियाली के बीच चेन पुलींग होने की चौंकाने वाली बात सामने आई है। गांधीधाम से ट्रेन रवाना होकर और रात को १२.५५ बजे के करीब ट्रेन की चेन पुलिंग होने से तीन मिनट के लिए ट्रेन रूकी थी। भचाऊ से सामखीयाली के बीच यह हत्या की पूरी घटना हुई थी। सूरजबारी पुल के पास ट्रेन में उपस्थित रेलवे के कर्मचारियों को जानकारी मिलने पर वह तुरंत कोच में पहुंच गये। ट्रेन में तीन जिंदा कार्टिस, २ फटे कार्टीस और एक फूटी बुलेट मिलने का सीआईडी क्राइम और रेलवे के डीजी आशिष भाटिया ने मीडिया के समक्ष चौकाने वाला खुलासा किया। डीजी आशिष भाटिया ने आगे बताया है कि, जयंती भानूशाली की हत्या मामले में सीट के सात अधिकारियों की विशेष टीम पूरे मामले की जांच करेगी। प्राथमिक जांच के दौरान ट्रेन के कोच में से तीन जिंदा कारतूस, दो फटे कारतूस और एक फूटी बुलेट मिली है। जिसमें ७.६५ एमएम की बुलेट हत्या में इस्तेमाल की गई होने का सामने आया है। बुलेट का आगे का हिस्सा और सप्लीन्टर मिला है। इस हत्या में कन्ट्री मेइड वेपन इस्तेमाल किए गया हो ऐसा लग रहा है। इतना ही नहीं, जयंती भानूशाली की हत्या एकदम निकट से यानी कि प्वाइंट ब्लैंक रेंज से की गई हो ऐसा लगता है। पुलिस ने मालिया और अन्य रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फूटेज लेकर हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। यह पूरी हत्या की जांच में शहर क्राइमब्रांच, एटीएस, सीआईडी, आरपीएफ सहित की टीमें भी शामिल होगी और केस में मदद करेगी। हत्या के समय ट्रेन के कोच में भानूशाली के साथ पवन मौर्य नाम का पैसेन्जर था, इसकी पूछताछ और जांच शुरू कर दी है और पुलिस इसके आधार पर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा, परिजनों द्वारा छबील पटेल के विरूद्ध जो गंभीर आरोप लगाया गया है,

बैंकों सहित के कार्यालयों के कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन

अहमदाबाद। केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में ३५ जितने ट्रेड यूनियन काउन्सील के ऐलान के तहत आज से बैंकों, कैमिस्ट्स, पोस्ट ऑफिस, बीमा ऑफिस, आंगनवाड़ी सहित के कर्मचारियों की दो दिन की हड़ताल पर चले गये। बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों, पोस्ट विभाग के कर्मचारियों सहित की ऑफिस के कर्मचारियों ने विभागीय स्तर पर अपनी मांगों के संदर्भ में उग्र विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। बैंकों के कर्मचारियों ने विशाल रैली और नारेबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोस्ट विभाग के कर्मचारियों ने भी नवरंगपुरा पोस्ट ऑफिसर, जीपीओ सहित के स्थलों पर विरोध कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। बैंकों से लेकर फैक्टरी-कारखानों में हड़ताल को लेकर रोजाना कामकाज ठप हो गया। विशेष करके दो दिन की हड़ताल के दौरान बैंकों के करोड़ों व्यवहार अटक जाने की स्थिति बनी है। बैंकों, पोस्ट ऑफिस सहित के कार्यालयों के कर्मचारियों की यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल को रेलवे सहित के देश के दस जितने बड़े मजदूर यूनियन ने समर्थन देने की घोषणा की है। हड़ताल की वजह से अहमदाबाद में १५०० करोड़ रुपये का बैंक क्लीयरिंग ठप हो जाने की संभावना है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)